सुविचार
खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दुःख होता है।
-चाणक्य

हैलो सरकार

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉन ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें
फोन: 0141-2202717
मो: 9214203182
वाट्सप नं. 9928078717

वर्ष-23 | अंक-265 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, शुक्रवार 30 मई , 2025 | पृष्ठ-4 | मूल्य: 2.50

सीएम भजनलाल शर्मा का निर्णय

राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं अभियोजन स्वीकृति के 16 प्रकरणों का निस्तारण

सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 9 अधिकारियों की पेंशन रोके जाने की कार्यवाही की गई है तथा 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन भी किया गया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार एवं कदाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए राज्य सेवा के

अधिकारियों के विरूद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं अभियोजन स्वीकृति के 16 विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण किया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अंतर्गत 5 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की तथा धारा 17-ए के एक प्रकरण में विस्तृत जांच एवं अनुसंधान की अनुमति प्रदान की है। इसी तरह कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न के प्रकरण में दोषी अधिकारी को सेवा से हटाया गया है। वहीं, पद के दुरुपयोग के साथ राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाने की जांच के एक प्रकरण में आरोपित अधिकारी को राजकीय सेवा से बर्खास्त किया गया है।

इसी तरह सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 9 अधिकारियों की पेंशन रोके जाने की कार्यवाही की गई है तथा 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन भी किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सेवारत 3 अधिकारियों के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के तहत 2 वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का निर्णय किया गया है। वहीं, एक प्रकरण में प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए 17 सीसीए में प्रदत्त दंड को यथावत रखा गया है।

महाराणा प्रताप हमारे लिए प्रेरणापुंज, नई पीढ़ी में आदर्शों का हो संचार- सीएम भजनलाल शर्मा

चित्तौड़गढ़। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मेवाड़ शक्ति, भक्ति, त्याग और तपस्या की भूमि है। मेवाड़ की धरा स्वाभिमान और शौर्य की एक अमिट मिसाल है। इस भूमि पर आकर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप हमारे लिए प्रेरणापुंज है, जिन्होंने सदैव सत्य, धर्म और राष्ट्रहित के मार्ग पर चलना सिखाया है। नई पीढ़ी में ऐसे आदर्शों एवं संस्कारों का संचार होना चाहिए। शर्मा गुरूवार को चित्तौड़गढ़ के भूपालसागर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर मूर्ति अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेवाड़ की इस गौरवशाली धरा की महान विभूतियों वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, अद्वितीय बलिदान की प्रतिमूर्ति मां पन्नाधाय और वीर योद्धा राणा पूंजा की प्रतिमाओं के अनावरण का यह अवसर आज के दिन को स्वर्णाक्षरों में अंकित करता है।

मुख्यमंत्री ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को नमन करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप पराक्रमी एवं स्वाभिमानी थे तथा उन्होंने

कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनका नाम सुनते ही धमनियों में शौर्य और पराक्रम का रक्त प्रवाहित होने लगता है, मस्तक गर्व और स्वाभिमान से ऊंचा हो उठता है।

महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित कर रही राज्य सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार महाराणा प्रताप के संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर एवं उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित कर रही है ताकि पर्यटक महाराणा प्रताप की शूरवीरता की गाथा अपने साथ लेकर जाए। साथ ही हमारी सरकार प्रदेश में कोच और खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है।

मेवाड़ ने त्याग, साहस और राष्ट्रभक्ति से इतिहास को गौरवशाली बनाया

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेवाड़ की धरा महाराणा प्रताप के साथ ही मां पन्नाधाय एवं राणा पूंजा की धरती है, जिन्होंने दुनिया को कर्तव्यनिष्ठा, शौर्य और अनूठे बलिदान का परिचय दिया। आज का यह दिन भी हमें त्याग, साहस और राष्ट्रभक्ति से हमारी सभ्यता को गौरवशाली बनाने वाले वीरों की याद दिलाता है।

कार्यक्रम में सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम दक, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, सांसद सीपी जोशी, सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे ।

मुख्यमंत्री ने किए करेड़ा पार्श्वनाथ मंदिर में दर्शन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भूपाल सागर स्थित करेड़ा पार्श्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और देश एवं प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित संतों से आशीर्वाद भी लिया।

राज्यपाल से मिला बेनीवाल का प्रतिनिधिमंडल

एसआई भर्ती रद्द करने व आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग

जयपुर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के अध्यक्ष व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस उप निरीक्षक (एसआई) भर्ती 2021 को रद्द करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के पुनर्गठन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।

राजभवन में हुई मुलाकात के दौरान सांसद बेनीवाल ने एसआई

भर्ती में हुए भ्रष्टाचार के तथ्यों को विस्तार से राज्यपाल के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस भर्ती की नींव ही भ्रष्टाचार पर रखी गई है और इसके बावजूद राज्य सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही, जो बेहद चिंताजनक है।

आरपीएससी पर भी गंभीर आरोप

सांसद ने आरपीएससी की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए राज्यपाल को अवगत कराया कि यह संवैधानिक संस्था अब भ्रष्टाचार की शरणस्थली बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग के सदस्य से लेकर चेयरमैन तक कई पेपर लीक प्रकरणों में संलिप्त रहे हैं। उन्होंने कहा कि संस्था की गरिमा की रक्षा के लिए इसका पूर्ण पुनर्गठन आवश्यक है।

राज्यपाल से मिला सकारात्मक आश्वासन

राजभवन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद बेनीवाल ने कहा कि राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने एसआई भर्ती व आरपीएससी से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राज्य के विकास से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हुए सकारात्मक आश्वासन दिया है।

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे

सांसद बेनीवाल ने चेतावनी दी कि अगर राज्य स्तर पर सुनवाई नहीं हुई, तो वे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं के हितों की रक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।

प्रतिनिधिमंडल में ये रहे शामिल

प्रतिनिधिमंडल में सांसद बेनीवाल के साथ शंकरलाल नारोलिया, छुट्टन यादव, ताराचंद रेगर, लादूराम गोदारा, विकास विधूड़ी, भूमि सियोल, धीरज शर्मा, जनार्दन जोशी समेत अन्य लोग शामिल रहे।

शहीद स्मारक पर भी पहुंचे सांसद, कहा-संघर्ष जारी रहेगा

इसी दिन शाम को सांसद हनुमान बेनीवाल शहीद स्मारक पर चल रहे धरने में भी पहुंचे। उन्होंने वहां उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए RLP का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चुनाव पूर्व किए गए वादों को भुला चुकी है, जिसकी जानकारी राज्यपाल को भी दी गई है।

ऑपरेशन शील्ड के तहत 31 मई को होगा मॉक ड्रिल अभ्यास, युद्ध जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी

जयपुर। पहले 7 मई को हुई मॉक ड्रिल में कई खामियां सामने आई थीं, जिन्हें सुधारने के उद्देश्य से यह अभ्यास दोहराया जा रहा है। ब्लैकआउट एक्सरसाइज में रात को एक समय पर पूरे इलाके की लाइट बंद करवाई जाएगी ताकि युद्ध जैसी स्थिति में प्रतिक्रिया का आकलन किया जा सके।

राजस्थान में एक बार फिर हवाई हमलों से बचाव और आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन शील्ड के तहत होने वाली इस अभ्यास की नई तारीख 31 मई तय की है। इससे पहले यह अभ्यास 29 मई को प्रस्तावित था, लेकिन गृह मंत्रालय ने इसे स्थगित कर दिया था।

गृह विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, यह मॉक ड्रिल प्रदेश के सभी 41 जिलों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक जिले में एक चयनित स्थान पर मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। इसमें हवाई हमलों से बचाव, नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना, सुरक्षा बलों की त्वरित प्रतिक्रिया, और इमरजेंसी सेवाओं की तत्परता का आकलन किया जाएगा।

पिछली मॉक ड्रिल में रही थीं खामियां

इससे पहले 7 मई को भी राज्यभर में मॉक ड्रिल की गई थी, जिसमें सायरन बजाकर हवाई हमले की चेतावनी दी गई थी और नागरिकों को अलर्ट किया गया था। हालांकि उस अभ्यास में कई जिलों से खामियों की शिकायतें सामने आई थीं। कहीं समय पर सूचना नहीं मिली, तो कहीं सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी देखने को मिली। इन्हीं खामियों को सुधारने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने अब मॉक ड्रिल दोहराने का फैसला लिया है।

ब्लैकआउट एक्सरसाइज भी होगी

31 मई की मॉक ड्रिल के दौरान रात में एक तय समय पर ब्लैकआउट भी किया जाएगा। ब्लैकआउट एक्सरसाइज का उद्देश्य यह देखना है कि अगर युद्ध की स्थिति में दुश्मन देश हवाई हमला करता है, तो अंधेरे में किस तरह से आम लोग और प्रशासनिक इकाइयां व्यवहार करते हैं। पिछले अभ्यास में लोगों से 15 मिनट तक अपने घर, दुकानों और दफ्तरों की लाइटें बंद रखने की अपील की गई थी, जिसे अधिकांश स्थानों पर सफलता भी मिली थी।

भारत-पाक तनाव की पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सात मई को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (क्ष्य) और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। इस अभियान को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था, जिसमें लगभग 100 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया गया था। इसके बाद से भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है।

गृह विभाग की ओर से अब जिलों को मॉक ड्रिल के लिए नये निर्देश भेजे जा रहे हैं। सिविल डिफेंस, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य आपातकालीन सेवाएं इस अभ्यास की तैयारियों में जुट गई हैं। मॉक ड्रिल के दौरान किसी भी अफवाह से बचने के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग के माध्यम से जनजागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। राजस्थान सरकार और केंद्र दोनों इस अभ्यास को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं, ताकि किसी भी संभावित आपदा या युद्ध जैसे हालात में आम नागरिकों की जानमाल की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के पीए से जुड़े सभी की होगी जांच-गजेंद्र सिंह

जयपुर। राजस्थान सरकार के एक कर्मचारी को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में जैसलमेर से पकड़ा गया है। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है। पकड़ा गया शख्स शाकुर खान है, जो जिला रोजगार कार्यालय में काम करता है। राजस्थान सरकार के एक कर्मचारी को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में जैसलमेर से हिरासत में लिया गया है। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी। हिरासत में लिया गया शख्स शाकुर खान है, जो जिला रोजगार कार्यालय में काम करता है। उसे बुधवार रात खुफिया विभाग की टीम ने सुरक्षा से जुड़ी जानकारी के आधार पर पकड़ा। इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के निजी सचिव को जासूसी के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। इसकी ठीक से जांच होकर जितने भी लोग उसके साथ जुड़े हैं, उन सब की जांच करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए।

शातिर नकबजन चढ़ा मुरलीपुरा पुलिस के हत्थे, 39.19 ग्राम सोना-430 ग्राम चांदी व कार बरामद

जयपुर। मुरलीपुरा थाना पुलिस ने नकबजनी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी जितेन्द्र सोनी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी गई 430 ग्राम चांदी, 39.19 ग्राम सोना तथा वारदात में प्रयुक्त वाहन कार बरामद की है।

जिला जयपुर पश्चिम के पुलिस उपायुक्त अमित कुमार, आईपीएस द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों की पालना में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक सिंघल व सहायक पुलिस आयुक्त सुरेन्द्र सिंह राणावत के सुपरविजन में मुरलीपुरा थाना प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कुरील के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।

इस टीम में विजय सिंह सउनि, झाबरमल सउनि, करण सिंह हैडकॉन्स्टेबल, रोहिताष्व, विनय कुमार, पुरणमल व सन्नी जैसे कर्मठ पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया। टीम को हाल ही में दर्ज प्रकरण संख्या 217/25 अंतर्गत

धारा 305 बीएनएस में दर्ज नकबजनी की वारदात के आरोपी की तलाश और माल-मशरूका की बरामदगी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पुलिस टीम ने आरोपी की पहचान व लोकेशन की पुष्टि के लिए करीब 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया। इसी तकनीकी निगरानी के माध्यम से आरोपी जितेन्द्र सोनी तक पुलिस पहुंच सकी। पूछताछ में उसने जुर्म कबूलते हुए चोरी की गई चांदी व सोने के जेवरात के साथ वारदात में प्रयुक्त कार के बारे में खुलासा किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए समस्त चोरी गया माल बरामद कर लिया है।

थाना मुरलीपुरा पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है, जिससे अन्य वारदातों के खुलासे की भी संभावना है। पुलिस टीम की इस तत्परता व सूझबूझ की सराहना की जा रही है।

राजस्थान के सभी 190 शहरी निकायों में एक साथ होगा चुनाव, सामने आई संभावित तारीख आरक्षण

जयपुर। स्थानीय स्वशासन (LSG) विभाग ने राज्य सरकार के निर्देशों के बाद 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच राजस्थान भर में सभी 190 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। यह पहली बार होगा जब राज्य सभी नगर निगमों के चुनाव एक साथ कराएगा और यह 'एक राज्य, एक चुनाव' मॉडल को लागू करने की योजना का हिस्सा है। राजस्थान के स्त्र मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ने बताया कि राज्य सरकार साल के अंत तक सभी शहरी स्थानीय निकायों (ख्र) के बोर्ड बनाना चाहती है। इसे पूरा करने के लिए, सभी यूएलबी के चुनाव और मतगणना प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी होनी चाहिए। खर्रा ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से वोटिंग के लिए तारीखें तय करना राज्य चुनाव आयोग पर निर्भर है।

बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में एलएसजी मंत्री ने जोधपुर, भरतपुर और जयपुर संभागों में शहरी निकायों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन पर चर्चा की। विभाग के एक अधिकारी ने कहा, हम शहरी प्रशासन को अधिक प्रभावी, जिम्मेदार और समावेशी बनाने के लिए परिसीमन प्रक्रिया का संचालन कर रहे हैं।

परिसीमन के बाद मतदाता सूची सुधार

चुनाव समय-सीमा में कई प्रमुख चरण हैं। परिसीमन प्रक्रिया जून तक पूरी होने वाली है, जिसके बाद विभाग मतदाता सूची को संशोधित करेगा और चुनाव तिथियों को अंतिम रूप देने के लिए राज्य चुनाव विभाग के साथ समन्वय करेगा।

लॉटरी सिस्टम से लागू होगा आरक्षण

सितंबर में जिला कलेक्टरेट महापौर और पार्षद दोनों पदों के लिए एससी, एसटी, ओबीसी और महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण निर्धारित करने के लिए लॉटरी आयोजित करेंगे। लॉटरी प्रणाली के बारे में बताते हुए, एलएसजी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यह प्रक्रिया निर्धारित करेगी कि कौन से महापौर पद विशिष्ट श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगे और कौन से सामान्य उम्मीदवारों के लिए खुले रहेंगे। यह पार्षद कोटा के साथ-साथ आरक्षित और सामान्य दोनों श्रेणियों में महिलाओं के आरक्षण का भी निर्धारण करेगा।

सितंबर के बाद उम्मीदवारों की घोषणा

व्यापक चुनावी अभ्यास का उद्देश्य सभी जनसांख्यिकीय क्षेत्रों में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए स्थानीय शासन को सुव्यवस्थित करना है। सितंबर में लॉटरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकेंगे।

राजस्थान के 4 मरीजों में कोरोना के नए वैरिएंट की पुष्टि

जयपुर। राजस्थान के चार मरीजों में कोरोना के नए वैरिएंट की पुष्टि हुई है। सवाईमानसिंह मेडिकल कॉलेज से पिछले दिनों इनके सैंपल पुणे की नेशनल वायरोलॉजी लैब में भेजे गए थे। इनमें ओमिक्रॉन के सब वैरिएंट एक्सएफजी के 2 और एलएफ.7.9 के 2 केस हैं।

देश के कुछ राज्यों में इन वैरिएंट के मामले इस समय अधिक आ रहे हैं। इसके अलावा जेएन.1 और एनबी.1.8.1 सीरीज के केस भी मिल रहे हैं। कॉलेज प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी के अनुसार यह वैरिएंट अधिक गंभीर नहीं हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

विभाग के अनुसार गुरूवार को राज्य में 15 नए केस मिले हैं, जिनमें 9 जयपुर, 4 उदयपुर और 2 जोधपुर के हैं।

कुल मरीजों की संख्या 54

प्रदेश में इस वर्ष कुल मरीजों की संख्या 54 हो गई है। 13 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें 3 जयपुर के अस्पतालों और 10 एम्स जोधपुर में भर्ती हैं। वहीं दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि केंद्र के अनुसार कोरोनावायरस का वर्तमान में सामने आया वैरियंट घातक नहीं है। पर आम जनता खांसी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षण नजर आने पर सावधानी बरतें। चिकित्सा संस्थान जाकर आवश्यक परामर्श, जांच एवं उपचार जरूर लें।

हिन्दी पत्रकारिता को व्यवसाय नहीं, मिशन बनाना होगा

विद्यार्थीजी के समाचार पत्र प्रताप से क्रांतिकारियों को काफी बल मिला। मुंशी प्रेमचंद महान् लेखक-कहानीकार होने के साथ-साथ हिन्दी के क्रांतिकारी एवं जुझारू पत्रकार थे, उनकी पत्रकारिता भी क्रांतिकारी थी, लेकिन उनके पत्रकारीय योगदान को लगभग भूला ही दिया गया है। जंगे-आजादी के दौर में उनकी पत्रकारिता ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध ललकार की पत्रकारिता थी। वे समाज की कुरीतियों एवं आडम्बरों पर प्रहार करते थे तो नैतिक मूल्यों की वकालत भी करते थे। मेरा सौभाग्य है कि मैं राजस्थान के यशस्वी पत्रकार स्व. श्रीरामस्वरूप गर्ग के पुत्र होने के नाते विरासत में पत्रकारिता के मूल्यों को आत्मसात करने का मौका मिला।

(लेखक- ललित गर्ग)

(हिन्दी पत्रकारिता दिवस- 30 मई, 2025)

भारत में हिन्दी पत्रकारिता की न केवल आजादी के संघर्ष में बल्कि उससे पूर्व के गुलामी की बेड़ियों में जकड़े राष्ट्र की संकटपूर्ण स्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, नये बनते भारत में यह भूमिका अधिक महसूस की जा रही है, क्योंकि तब से आज तक समाज की आवाज उठाने, सत्ता से सवाल पूछने और जनभावनाओं को मंच देने में इसका योगदान अविस्मरणीय रहा है। हिंदी पत्रकारिता या स्थानीय पत्रकारिता, लोगों को उनकी भाषा में जानकारी उन तक पहुँचाता है और देश भर में ज्ञान के व्यापक प्रसार को सुगम बनाता है। हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, दरअसल दो शताब्दी पूर्व ब्रिटिशकालीन भारत में जब तत्कालीन हिन्दुस्तान में दूर दूर तक मात्र अंग्रेजी, फ़ारसी, उर्दू एवं बांग्ला भाषा में अखबार छपते थे, तब देश की राजधानी फ़कलकताफ़ से हिन्दी भाषा में 'उदन्त मार्तण्ड' के नाम से पहला हिन्दी समाचार पत्र वर्ष 1826 को छपा था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे साप्ताहिक के तौर पर शुरू किया था। इसके प्रकाशक और संपादक भी वे खुद थे। भले ही अब यह समाचार पत्र बंद हो गया है, लेकिन इसने हिंदी पत्रकारिता के सूर्य को उदित कर दिया था जो आज भी देदीप्यमान है।

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत और बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदी के अनेक दैनिक समाचार पत्र निकले जिनमें हिन्दुस्तान, भारतोदय, भारतमित्र, भारत जीवन, अभ्युदय, विश्वमित्र, आज, प्रताप, विजय, वीर अर्जुन आदि प्रमुख हैं। बीसवीं शताब्दी के चौथे-पांचवें दशकों में अमर उजाला, आर्यावर्त, नवभारत टाइम्स, नई दुनिया, जागरण, पंजाब केसरी, नव भारत आदि प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्र सामने आए। लोकतंत्र में मीडिया चौथे स्तंभ के रूप में खड़ा है, पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम देश की वर्तमान स्थिति से अवगत रहते हैं। पत्रकार अथक परिश्रम करते हैं, ताकि समाचार हमारे घर तक तुरंत पहुंचे। चाहे अखबारों के जरिए हो, टीवी चैनलों के जरिए हो या सोशल मीडिया के व्यापक प्रभाव के जरिए, नित-नये बनते एवं बदलते समाज में पत्रकारिता की शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और सूचित संवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

हिन्दी पत्रकारिता में क्रांतिकारिता का रंग गणेश शंकर विद्यार्थी ने भरा था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से 9 नवंबर 1913 को 16 पृष्ठ का 'प्रताप' समाचार पत्र शुरू किया था। यह काम शिव नारायण मिश्र, गणेश शंकर विद्यार्थी, नारायण प्रसाद अरोड़ा और कोरोनेशन प्रेस के मालिक यशोदा नंदन ने मिलकर किया था। शिव नारायण मिश्र और गणेश शंकर विद्यार्थी ने 'प्रताप' को अपनी कर्मभूमि बना लिया। विद्यार्थीजी के समाचार पत्र प्रताप से क्रांतिकारियों को काफी बल मिला। मुंशी प्रेमचंद महान् लेखक-कहानीकार होने के साथ-साथ हिन्दी के क्रांतिकारी एवं जुझारू पत्रकार थे, उनकी पत्रकारिता भी क्रांतिकारी थी, लेकिन उनके पत्रकारीय योगदान को लगभग भूला ही दिया गया है। जंगे-आजादी के दौर में उनकी पत्रकारिता ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध ललकार की पत्रकारिता थी। वे समाज की कुरीतियों एवं आडम्बरों पर प्रहार करते थे तो नैतिक मूल्यों की वकालत भी करते थे। मेरा सौभाग्य है कि मैं राजस्थान के यशस्वी पत्रकार स्व. श्रीरामस्वरूप गर्ग के पुत्र होने के नाते विरासत में पत्रकारिता के मूल्यों को आत्मसात करने का मौका मिला। उन्होंने 1936 एवं उसके बाद के दौर में 'राष्ट्रवाणी' एवं 'परिवर्तन' जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं सम्पादन किया। वे राजस्थान के प्रतिष्ठित दैनिक नवज्योति के साप्ताहिक रूप में निकले प्रारंभिक अंकों के सम्पादक रहे। इसका प्रारंभ पण्डित जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिव रहे श्री रामनारायण चौधरी ने किया था।

आज जबकि हिन्दी देश एवं दुनिया में सर्वाधिक बोली एवं प्रयोग की जाने वाली तीसरी भाषा बन चुकी है, ऐसे में सहज ही हिन्दी पत्रकारिता का मूल्य बढ़ा है। निस्संदेह, सजग, सतर्क और निर्भीक हिन्दी पत्रकार एवं पत्रकारिता एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाकर सत्ताधीशों को राह ही दिखाता है। अकबर इलाहाबादी ने इसकी ताकत एवं महत्व को इन शब्दों में अभिव्यक्ति दी है कि 'न खींचो कमान, न तलवार निकालो, जब तोप हो मुकाबिल तब अखबार निकालो।' उन्होंने इन पंक्तियों के जरिए हिन्दी पत्रकारिता को तोप और तलवार से भी शक्तिशाली बता कर इनके इस्तेमाल की बात कह गए हैं। अर्थात कलम को हथियार से भी ताकतवर बताया गया है। पर खबरनवीसों की कलम को तोड़ने, उन्हें कमजोर करने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निस्तेज करने के लिए बुरी एवं स्वार्थी ताकतें सत्ता, तलवार और तोप का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन तलवार से भी धारदार कलम इसीलिये इतनी प्रभावी है कि इसकी वजह से बड़े-बड़े राजनेता, उद्योगपतियों और सितारों को अर्श से फर्श पर आना पड़ा।

हिन्दी पत्रकार एवं पत्रकारिता कई संकटों का सामना कर रहे हैं- संघर्ष और हिंसा, आतंक एवं अलगाव, साम्प्रदायिकता एवं अंधधार्मिकता, युद्ध एवं राजनीतिक वर्चस्व, गरीबी एवं बेरोजगारी, लगातार सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ, पर्यावरणीय संकट और लोगों के स्वास्थ्य और भलाई के लिए चुनौतियाँ आदि जटिलतर स्थितियों के बीच हिन्दी पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोकतंत्र, कानून के शासन और मानवाधिकारों को आधार देने वाली संस्थाओं पर गंभीर प्रभाव के कारण ही यह भूमिका महत्वपूर्ण है। बावजूद इसके हिन्दी पत्रकारिता की स्वतंत्रता, पत्रकारों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगातार हमले हो रहे हैं। कभी-कभी भारत में हिन्दी पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर सख्त पहरे जैसा भी प्रतीत होता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि बड़ी सचाई है कि इन्हीं पत्रकारों के बल पर हमें आजादी मिली है। पत्रकारिता लोकहित में सरकार को कदम उठाने का रास्ता सुझाती रहती है, इसीलिए उसकी विश्वसनीयता होती है। मगर सरकारें जब उसके मूल स्वभाव को ही बदलने का प्रयास करती हैं, तो उसकी विश्वसनीयता पर प्रहार करती हैं। ऐसे में पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ न होकर प्रचारतंत्र में तब्दील होने लगती है। पत्रकारिता आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों को दूर करने में मदद करती है। उसका लाभ उठाने के बजाय अगर उसका गला घोटने का प्रयास होगा, तो सही अर्थों में विकास का दावा नहीं किया जा सकता, नया भारत-सशक्त भारत निर्मित नहीं किया जा सकता। अगर कोई सरकार सचमुच उदारवादी और लोकतांत्रिक होगी, तो वह आलोचना से कुछ सीखने का प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी हिन्दी पत्रकारिता के प्रति हमारे अविश्वसनीय समर्थन को दोहराने की बात कही है जो लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है।'

हिन्दी पत्रकारिता कभी मिशन था, आज व्यवसाय बन गया है। आजादी के आंदोलन तक मिशन रहा। धीरेल्धीरे इसमें व्यापारी आने लगे। औद्योगिक घराने उतर गए। इनका उद्देश्य समाज सेवा नही रहा, व्यापार हो गया। ये व्यापार करने लगे। वह छापने लगे जिससे इन्हें लाभ हो। डिजिटल युग में टीआरपी और व्यूज़ ही सफलता का पैमाना बन गए हैं। गंभीर पत्रकारिता की जगह सनसनीखेज खबरें, गॉसिप, और 'डिबेट तमाशों' ने ले ली है। तथ्य की जगह धारणा, विश्लेषण की जगह उत्तेजना, और संवाद की जगह शोर ने कब्जा कर लिया है। एंकर शोर मचाकर चीखकर पाठकों को आकर्षित करन में लगे हैं। हिन्दी पत्रकारिता ऐसी अनेक चुनौतियों एवं विसंगतियों का सामना कर रही है। बीते कुछ वर्षों में पत्रकारिता का स्तर चिंताजनक रूप से गिरा है, जबकि पत्रकारों की प्रसिद्धि, प्रभाव और पहुंच पहले से कहीं अधिक बढ़ी है। यह विरोधाभास क्यों? पत्रकार बड़े होते जा रहे हैं, पर पत्रकारिता एवं उसके मूल्य-मानक क्यों सिकुड़ रहे है? आज फेसबुक पत्रकार, न्यूज पोर्टल चलाने वाले पत्रकार, यूट्यूब चैनल चलाने वाले पत्रकारों की देश में बाढ़ सी आ गई है। टीवी पत्रकारिता का वर्चस्व बढ़ रहा है, बड़े एवं बहु-संस्करणों के दैनिक अखबार भी तेजी से बढ़ रहे हैं। आन लाइन समाचार पत्रों की रोज गिनती बढ़ती जा रही है। जिसे देखो पत्रकारिता कर रहा है। इतना सब होने के बावजूद पिछले कुछ साल में खबर एवं हिन्दी पत्रकारिता की विश्वसनीय घटी है। पत्रकारिता का स्तर गिरा है। पत्रकार का सम्मान घटा है। पहले माना जाता कि अखबार में छपा है तो सही होगा, किंतु मीडिया में आई खबर की आज कोई गारंटी देने को तैयार नहीं। पहले हिन्दी पत्रकारिता वैचारिक-क्रांति होती थी, आज खबर प्रधान बन गयी है, विचार लुप्त है। हिन्दी पत्रकारिता दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब उसे व्यवसाय नहीं, मिशन के तौर पर नये व्यक्ति, नये समाज, नये राष्ट्र का प्रेरक बनायेंगे।

संपादकीय

ट्रंप की वक्र दृष्टि

अपने बेतुके फैसलों व टैरिफ वार से तमाम अर्थव्यवस्थाओं को हिलाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की वक्र दृष्टि अब अमेरिका के नामी-गिरामी विश्वविद्यालयों पर भी पड़ी है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र होने का दंभ भरने वाले अमेरिका में विश्वविद्यालय परिसरों में लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का गला घोंटा जा रहा है। अब अमेरिका में उच्च शिक्षा का सपना देखने वाले भारत व दुनिया के तमाम देशों के छात्रों के लिये ट्रंप प्रशासन ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हाल के दिनों में प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालयों पर मनमाने फैसले थोपे व कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए, जो विश्वविद्यालयों के परिसरों में अभिव्यक्ति की आजादी पर नकेल कसने की ही कवायद थी। दलील दी गई कि फलस्तीन का समर्थन करने वाले छात्र-छात्राओं की सूचना ट्रंप प्रशासन को दी जाए। इन्हीं बंदिशों के बाद अब ट्रंप सरकार ने दुनियाभर के अपने दूतावासों को स्टूडेंट वीजा की प्रक्रिया बंद करने का आदेश दिया है। ट्रंप सरकार की दलील है कि पहले आवेदक छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट की गहरी जांच की जाएगी। इस योजना पर काम चल रहा है। दरअसल, अमेरिकी सरकार द्वारा स्टूडेंट वीजा के लिये आवेदन करने वाले छात्रों की सोशल मीडिया गतिविधियों की गहन जांच तेज की जाएगी। इस फैसले से भारत समेत तमाम देशों के छात्रों की अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के सपने को आंच आ सकती है। अमेरिका सरकार इसके माध्यम से उन छात्रों के आवेदन को खारिज करने की तैयारी में है जिनके सोशल मीडिया अकाउंट में ट्रंप या अमेरिका की नीतियों की आलोचना की सामग्री होगी। जाहिर है ऐसे छात्रों को अमेरिका के विश्वविद्यालयों में दाखिला नहीं दिया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 में करीब तीन लाख से अधिक भारतीय छात्र अध्ययनरत थे। अपने सपनों को पूरा करने के लिये हजारों भारतीय प्रतिभाएं हर साल अमेरिका का रुख करती हैं। अमेरिका के इस फैसले से उन छात्रों को दिक्कत होगी जो इस साल अगस्त से शुरू होने वाले सत्र का हिस्सा बनना चाह रहे थे। दरअसल, अमेरिका सरकार द्वारा अपने दूतावासों को कहा गया है कि वीजा के लिये पेश किए गए नये आवेदनों को रोक दें। उन पर सोशल मीडिया खातों की जांच के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा। यहां उल्लेखनीय है कि ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पहले से पढ़ रहे सैकड़ों छात्रों के वीजा इस आरोप के बाद निरस्त कर दिए कि उन्होंने इस्राइल विरोधी आंदोलन में शिरकत की थी। इनमें वे छात्र भी शामिल थे जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फलस्तीनियों के पक्ष में पोस्ट डाली थी। सरकार की दलील थी कि इन छात्रों को पढ़ाई के लिये वीजा मिला था न कि राजनीतिक मुद्दों में सक्रियता के लिये। उल्लेखनीय है कि कई भारतीय छात्र भी इस फैसले की चपेट में आए हैं। इसके चलते ही अमेरिकी दूतावासों को वीजा आवेदन करने वालों के सोशल अकाउंट की स्क्रीनिंग के आदेश दिए गए हैं। जांच के बाद छात्रों की गतिविधियों में अमेरिकी नीतियों का विरोध न होने पर वीजा दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस स्क्रीनिंग में इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, लिंक्डइन, टिकटॉक आदि सोशल मीडिया अकाउंट को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, वीजा पर सख्ती के अलावा पहले से अमेरिका में पढ़ रहे छात्रों के लिये नियम सख्त किए जा रहे हैं। यहां तक चेतावनी दी गई है कि नियमित कक्षाओं में न जाने वाले तथा ड्राप आउट का विकल्प चुनने वाले छात्रों के वीजा भी रद्द किए जा सकते हैं। उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट में अमेरिकी नीतियों की आलोचना करने से बचने की नसीहत दी गई है।

व्यवसायिकता ने निगल ली निष्पक्षता पत्रकारिता!

(लेखक- डा श्रीगोपाल नारसन)

(30 मई पत्रकारिता दिवस पर)

अब मिशनरी पत्रकारिता का दौर खत्म हो चुका है और मिशनरी की जगह व्यवसायिकता का कब्जा हो गया है,तभी तो पत्रकारिता पतन के कगार पर पहुंच गई है।लेकिन ब्रह्माकुमारीज जैसी संस्थाएं अभी भी पत्रकारिता को सकारात्मक मार्ग पर लाने के लिए भरसक प्रयत्न में जुटी हुई है।जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर लोकल स्तर पर भी पत्रकारों को बुलाकर उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देकर उन्हें नकारात्मक पत्रकारिता के दल दल से निकालने का सार्थक प्रयास कर रही है। क्षेत्रीय ,प्रादेशिक व राष्ट्रीय अखबारो व मीडिया चैनलों ने अधिकांशतः सत्ता की ताकत के साथ समझौता कर अपने एथिक्स को कही पीछे धकेल दिया है।जिस कारण इतिहास बनती मिशनरी पत्रकारिता को बचाने के लिए अब हमें नए सिरे से विचार करना होगा कि सुबह का अखबार कैसा हो? समाचार चैनलों पर क्या परोसा जाए? क्या नकारात्मक समाचारों से परहेज कर सकारात्मक समाचारों की पत्रकारिता संभव है ?क्या धार्मिक समाचारों को समाचार पत्रों में स्थान देकर पाठको को धर्मावलम्बी बनाया जा सकता है ? हाल ही में देश के लगभग 500 पत्रकारों ने ब्रहमाकुमारीज के ज्ञान सरोवर माउण्ट आबू में हुए मीडिया सम्मेलन में एक स्वर में निर्णय लिया कि व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय उन्नति के लिए उज्जवल चरित्र व सांस्कृतिक निर्माण के सहारे सकारात्मक समाचारों को प्राथमिकता देकर मीडिया सामग्री में व्यापक बदलाव किया जाए। सम्मेलन में विकास से सम्बन्धित समाचारों,साक्षता,संस्कृति,नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्य जैसे मुददों का समावेश कर स्वस्थ पत्रकारिता का लक्ष्य निर्धारित करने की मांग की गई थी। आज देशभर में 800 से अधिक चैनल चल रहे है। जिनमें से कई चैनल ऐसे है जो समाज के सुदृडीकरण के लिए खतरनाक है। इन चैनलों पर इतनी अश्लीलता दिखाई जाती है कि उसे पूरा परिवार एक साथ बैठकर नही देख सकता। ऐसे चैनलों पर कोई रोक भी नही है। इसलिए ऐसे चैनलों को ऐसी आपत्तिजनक सामग्री परोसने के बजाए समग्र परिवार हित की सामग्री परोसने पर इन चैनलों को विचार करना चाहिए।सम्मेलन में ऐसे समाचारों को परोसने से परहेज करने की सलाह दी गई थी जिसको चैनल पर देखकर या फिर अखबार में पढकर मन खराब होता हो या फिर दिमाग में तनाव उत्पन्न होता हो।बदलते दौर में हिन्दी पत्रकारिता के भी मायने बदल गए है। अपनी ताकत से दुनिया को मुठठी में करने के बजाए पत्रकारिता गली मोहल्लो तक सिकुडती जा रही है। अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का बताने वाले समाचार पत्र क्षेत्रीयता के दायरे में और क्षेत्रीय स्तर का बताने वाले समाचार पत्र स्थानीयता के दायरे में सिमटते जा रहे है। जो पत्रकारिता के लिए शुभ संकेत नही है। सही मायने में पत्रकारिता का अर्थ अपनी और दुसरों की बात को दूर तक पंहुचाना है।साथ ही यह भी जरूरी है कि किस धटना को खबर बनाया जाए और किसे नही? आज की पत्रकारिता बाजारवाद से ग्रसित होने के साथ साथ मूल्यों की दृष्टि से रसातल की तरफ जा रही है। बगैर कार्यक्रम हुए ही कपोल कल्पित कार्यक्रम की खबरे आज अखबारो की सुर्खिया बनने लगी है,सिर्फ नाम छपवाने के लिए जारी झूठी सच्ची विज्ञप्तियों के आधार पर एक एक खबर के साथ बीस बीस नाम प्रकाशित किये जाने लगे है जो पत्रकारिता की विश्वसनीयता को न सिर्फ प्रभावित कर रहे है बल्कि ऐसी पत्रकारिता पर सवाल उठने भी स्वाभाविक है। इसके पीछे अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि जितने ज्यादा नाम प्रकाशित होगे, उतना ही ज्यादा अखबार बिकेगा, लेकिन यह पत्रकारिता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नही है । ठीक यह भी नही है कि प्रसार संख्या बढाने की गरज से समाचार पत्र को इतना अधिक स्थानीय कर दिया जाए कि वह गली मोहल्ले का अखबार बन कर रह जाए।

आज हालत यह है कि ज्यादातर अखबार जिले और तहसील तक सिमट कर रह गए है। यानि एक शहर की खबरे दूसरे शहर तक नही पंहुच पाती।देश के राज्यो व जनपदों की सीमा बदलने के साथ ही पत्रकारिता भी सीमाओं की परिधि में सिकुड़ गई है। जिस कारण जिला और प्रदेश बदल जाने के कारण एक नगर की खबरे दूसरे तक नही पंहुच पाती है।इससे पाठक स्वयं को ठगा सा महसूस करता है। ऐसा नही है कि स्थानीय खबरो की जरूरत न हो, लेकिन यदि एक अखबार में लॉक डाउन से पहले 4से 6 पेज स्थानीय खबरो के होते थे जो अब दो पृष्ठों में सिमट कर रह गए है।इससे पाठक को क्षेत्रीय,राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरे कम पढने को मिल रही है, जो उनके साथ अन्याय है। वैसे भी खबर वही है, जो दूर तक जाए यानि दूरदराज के क्षेत्रो तक पढी जाए। दो दशक पहले तक स्थानीय खबरो पर आधारित अखबार बहुत कम थे। पाठक राष्ट्रीय स्तर के अखबारो पर निर्भर रहता था। वही लोगो की अखबार पढने में रूची भी कम थी। स्थानीय अखबारो ने पाठक संख्या तो बढाई है लेकिन पत्रकारिता के स्तर को कम भी किया है। आज पीत पत्रकारिता और खरीदी गई खबरो से मिशनरी पत्रकारिता को भारी क्षति हुई है। जिसे देखकर लगता है जैसे पत्रकारिता एक मिशन न होकर बाजार का हिस्सा बनकर गई हो। पत्रकारिता में परिपक्व लोगो की कमी,पत्रकारिता पर हावी होते विज्ञापन,पत्रकारो के बजाए मैनेजरो के हाथ में खेलती पत्रकारिता ने स्वयं को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जरूरी है पत्रकारिता निष्पक्ष हो लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है

ऐसी खबर जो सच होते हुए भी राष्ट्र और समाज के लिए हानिकारक हो, तो ऐसी खबरो से परहेज करना बेहतर होता है। पिछले दिनों देश में गोला बारूद की कमी को लेकर जो खबरे आई थी वह राष्ट्र हित में नही थी इसलिए ऐसी खबरो से बचा जाना चाहिए था। जस्टिस मार्कण्डेय काटजू का यह ब्यान कि पत्रकारिता को एक आचार संहिता की आवश्कयता है,अपने आप में सही है ,बस जरूरत इस बात कि है कि यह आचार संहिता स्वयं पत्रकार तय करे कि उसे मिशनरी पत्रकारिता को बचाने के लिए क्या रास्ता अपनाना चाहिए जिससे स्वायतता और पत्रकारिता दोनो बची रह सके। इसके लिए जरूरी है कि पत्रकार प्रशिक्षित हो और उसे पत्रकारिता की अच्छी समझ हो,साथ ही उसे प्रयाप्त वेतन भी मिले।ताकि वह शान के साथ पत्रकारिता कर सके और उसका भरण पोषण भी ठीक ढंग से हो।तभी मौजूदा पत्रकारिता अपने मानदण्डो पर खरी उतर सकती है और अपने मिशनरी स्वरूप को इतिहास बनने से बचा सकती है।इसके लिए हमे अपनी सोच में भी परिवर्तन करना होगा।जब तक हमारे अपने चरित्र ठीक नही होंगे,हम सात्विक नही होंगे, हम आध्यात्मिक नही होंगे तब पत्रकारिता में भी सकारात्मक बदलाव की उम्मीद नही की जा सकती।

(चिंतन-मनन)

सदाचार की परीक्षा

राजा अंग सिंह के पुत्र प्रवीण सिंह गलत संगति में पड़कर अनुचित कार्य करने लगा। चारों तरफ से उसकी शिकायतें आने लगीं। इससे राजा अत्यंत चिंतित हो गए। प्रवीण सिंह अभी बालक ही था, इसलिए राजा चाहते थे कि उसका स्वभाव बदले और भविष्य में वह एक नेक राजा बन सके।

वह उसे अपने गुरु सोमदेव के पास लेकर आए। सोमदेव ने युवराज को छह माह तक अपने आश्रम में छोड़ देने के लिए कहा। वह प्रतिदिन युवराज को अपने साथ रखते और उससे कई कार्य कराते। इसी तरह तीन महीने बीत गए। अब राजकुमार पर सुसंगति के साथ ही गुरुदेव की बातों का असर पड़ने लगा था। एक दिन गुरु बोले, पुत्र, ईश्वर हर जगह मौजूद है। याद रखो दुष्कर्म और पाप की सजा मिलती अवश्य है क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा होता है। जब तुम किसी प्रलोभन से पाप करने को उतारू हो तो वहीं ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करो। तुम हर जगह यह सोचो कि मेरा प्रभु मेरे सामने है।

वह ये बातें प्रतिदिन युवराज को बताते। एक दिन उन्होंने राजकुमार को एक खरगोश देकर उसे एकांत में ले जाकर मारने को कहा। युवराज खरगोश को लेकर कई स्थानों पर गया लेकिन उसकी गर्दन नहीं मरोड़ पाया। वह जब भी उसकी गर्दन पर हाथ रखता तो उसकी निरीह आंखों में उसे ईश्वर नजर आते। कई घंटों बाद वह वापस जीवित खरगोश को लेकर गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरु जी आप ही ने तो सिखाया है कि हर किसी में ईश्वर की उपस्थिति समझो। फिर मैं अकेला कैसे हो सकता हूं? इस खरगोश की भोली आंखों में मुझे ईश्वर की उपस्थिति नजर आई। इसलिए मैं इसे मार नहीं पाया। युवराज की बात सुनकर गुरु सोमदेव ने उसे गले से लगा लिया और बोले, पुत्र, आज तुम सदाचार और प्रेम की परीक्षा में पास हो गए हो। इसके बाद महाराज उसे अपने साथ ले गए।

विचार मंथन

राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट

(लेखक - सनत जैन/)

महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका

महाराष्ट्र मे डबल इंजन की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हजारों करोड़ के ठाणे ट्विन टनल और वसई एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट में पारदर्शिता की कमी को लेकर महाराष्ट्र सरकार को जमकर फटकारा है। इस परियोजना में मेघा इंजीनियरिंग नामक कंपनी को टेंडर देने का मामला सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। विश्व प्रसिद्ध एलएंडटी कंपनी को टेक्निकल कारणों से महाराष्ट्र सरकार ने एलएंडटी को अयोग्य ठहराया। चौंकाने वाली बात यह थी। एलएंडटी की बोली मेघा इंजीनियरिंग से करीब 3000 करोड़ रुपये कम की थी। मेगा इंजीनियरिंग को टेंडर देने के लिए एलएनटी को अक्षम बताकर 3000 करोड़ ज्यादा राशि में यह टेंडर मेगा इंजीनियरिंग को दिया गया। यह टेंडर एमएमआरडीए द्वारा जारी किया गया था। जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अधीन था। सुप्रीम कोर्ट ने इस चयन प्रक्रिया को मनमाना और अपारदर्शी बताते हुए कहा ,यह जनता के पैसे की बर्बादी है। एक तरह से यह रिश्वतखोरी और कदाचरण की ओर इशारा करता है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा सरकार अपनी एफडी तोड़कर ये पैसा नहीं दे रही है। यह टैक्सपेयर का धन है।इसकी जवाबदेही तय होगी। इस मामले की चर्चा इस वजह से और भी तेज हुई। क्योंकि मेघा इंजीनियरिंग ने 2019 से 2024 तक करीब 966 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। जिनमें से 644 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया। मेघा इंजीनियरिंग ने इस टेंडर के मिलने के बाद कंपनी ने 115 करोड़ के नए चुनावी बॉन्ड खरीदे। इस पर अदालत ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को समझ गई है। मेघा इंजीनियरिंग को क्यों 3000 करोड रुपए ज्यादा में टेंडर दिया गया। एलएनटी को तकनीकी कारणों से क्यों बाहर किया गया। पिछले एक दशक से केंद्र एवं डबल इंजन की सरकार जिन-जिन राज्यों में है। वहां पर विकास के नाम पर इसी तरह की कार्रवाई चल रही है। चुनावी बॉन्ड सत्ता में बैठे राजनीतिक दलों के लिए खुलेआम रिश्वत लेने के लिये नया जरिया बन गए थे? महाराष्ट्र सरकार की वित्तीय स्थिति पहले से ही खराब है। महाराष्ट्र सरकार के पास जरूरी योजनाओं के लिए जिसमें फसल खरीदने और किसानों को पैसा नहीं दे पा रही है। स्कूल गोद लो योजना के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। जिससे शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है।लाडली बहना योजना का भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में एक ही प्रोजेक्ट में 3000 करोड़ रुपये की मेघा इंजीनियरिंग पर जो कृपा महाराष्ट्र सरकार द्वारा बरसाई गई है। यह टैक्सपेयर्स और आम जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा नही है? सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को टेंडर रद्द करने, पुनर्निविदा की प्रक्रिया अपनाने का निर्देश महाराष्ट्र सरकार को दिया है। ऐसा नहीं होने पर न्यायालय के आदेश का इंतजार करने की चेतावनी महाराष्ट्र सरकार को दी है। यह मामला सिर्फ टेंडर की पारदर्शिता का नहीं, बल्कि सरकार की राजनीतिक एवं प्रशासनिक जवाबदेही का भी है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से स्पष्ट हो गया है, कि डबल इंजन की सरकारों में विकास के नाम पर जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उसमें किस लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है। चुनावी बांड के जरिए किस तरह से रिश्वत का नया खेल भारत में शुरू हुआ था। पिछले कुछ वर्षों से राम के नाम पर जिस तरह का भीड तंत्र तैयार किया गया है। भाजपा ने आम जनता के बीच यह छ बि बनाई है। भाजपा नेता ईमानदार हैं। विपक्ष भ्रष्टाचारी है। पिछले वर्षों में विपक्षी दलों की बेईमान और राम नाम जपने वालों को ईमानदार बताया गया है। राम के नाम पर जो लूट हो रही है, उसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट में इस केस के माध्यम से हुआ है।

धार्मिक उन्माद और राम के नाम पर डबल इंजन की सरकारें बनी है। अपनी जवाबदेही से बच रही हैं। एलएनटी जैसी संस्था जो तकनीकी के मामलों में भारत ही नहीं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्था के रुप में स्था पित है। जिसने राम मंदिर के निर्माण में महती भूमिका का निर्वाह किया है। उसे भी डबल इंजन की सरकार के मुख्य पदों पर बैठे हुए लोगों द्वारा अपने निजी और राजनीतिक लाभ के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता है।

सोने का भाव 90000 से नीचे आने की संभावना

नई दिल्ली।

शादी-ब्याह के इस मौसम में सोना अब भी 95,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर बना हुआ है, जिससे ग्राहकों और निवेशकों की जेब पर दबाव बना हुआ है। ले किन सोने के भाव में फिर से ` गिरावट की संभावना जताई जा रही है।` जिससे` निवेशकों और ग्राहकों की` चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि 9 जुलाई के बाद सोने के दामों में गिरावट आ सकती है। इसका मुख्य कारण है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आयात शुल्क के मुद्दे पर अनिश्चितता का समापन होने की संभावना। वैश्विक टैरिफ से जुड़े अनिश्चितता के हल हो जाने से निवेशकों के लिए सोने में बना दबाव कम हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा 3,270 डॉलर प्रति औंस के करीब सोने की कीमत संभावित रूप से 3,000 डॉलर तक गिर सकती है, जिससे घरेलू बाजार में सोने की कीमत 90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आ सकती है।

विदेश सचिव विक्रम ने वाशिंगटन में अमेरिकी उपमंत्री जेफरी से की मुलाकात

भारत-अमेरिका सहयोग को बढ़ाने पर विचार व्यक्त किए गए

वाशिंगटन।

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने अमेरिकी उपमंत्री जेफरी केसलर से वाशिंगटन में महत्वपूर्ण मुलाकात की। चर्चा में उभरती प्रौद्योगिकियों और उभरती क्षेत्रों में भारत-अमेरिका सहयोग को बढ़ाने पर विचार व्यक्त किए गए। भारतीय दूतावास ने साझा किया कि मिसरी ने तकनीकी और व्यापारिक सहयोग को मजबूत करने की बात कही। इससे पहले भारतीय मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के फॉलो-अप के तौर पर है। इस दौरे पर विक्रम मिसरी ने अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की थी और भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के लिए कहा। उन्होंने भी इंडिया-यूएस कॉम्पैक्ट के साथ एक नयी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर चर्चा की। यह सम्मेलन भारत और अमेरिका के बीच ताकतवर साझेदारी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है और दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यापारिक जीवन में नए दरवाजे खोल सकता है।

ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री में गिरावट, तीसरे नंबर पर

नई दिल्ली।

वाहन पोर्टल के अनुसार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने मई माह में बिक्री में गिरावट का सामना किया। इस साल कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 20 फीसदी रही, जबकि पिछले साल इस समय यह आंकड़ा 60 फीसदी था। जानकारों के मुताबिक 2025 के मई महीने में केवल 15,221 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 37,388 था। इसके विपरीत पुराने प्लेयर टीवीएस मोटर ने 25 फीसदी मार्केट शेयर के साथ पहले स्थान पर अपना स्थान बनाया, जबकि बजाज ऑटो दूसरे स्थान पर 22.6 फीसदी हिस्सेदारी के साथ थमा। एथर एनर्जी का मार्केट शेयर अप्रैल के 14.9 से घटकर मई में 13.1 फीसदी रह गया। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर इस साल 38 फीसदी गिरा है जबकि बुधवार को शेयर 0.7 फीसदी की तेजी के साथ 52.88 रुपए पर बंद हुआ। कंपनी ने इस साल सेल्स नंबर में गड़बड़ी और ट्रेड सर्टिफिकेट को लेकर विवादों में भी घिरी है। फरवरी में किए गए दावों के अनुसार कंपनी ने 25,000 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे और इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर में 28 फीसदी मार्केट शेयर हासिल किया।

भारत में 2027 तक 383 फीसदी बढ़ जाएगा एजेंटिक एआई का इस्तेमालः रिपोर्ट

नई तकनीक के जरिए मशीनें स्वतंत्रता से निर्धारण लेने के क्षमता से लाभान्वित होंगी

नई दिल्ली।

भारत में मानव संसाधन क्षेत्र के दिग्गजों का विचार है कि भविष्य में एजें टिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एजें` टिक एआई) के इस्तेमाल में वृद्धि देखने को मिल सकती है। अमे रिका में जारी की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2027 तक एजेंटिक एआई की मान्यता में 383 फीसदी की वृद्धि संभव है। इस नई तकनीक के जरिए मशीनें स्वतंत्रता से निर्धारण लेने के क्षमता से लाभान्वित होंगी। भारत में इस ` विभाग से संबं धित एक अे धिकारी को उम्मीद है कि एजेंटिक एआई के चलते उन्हें 24.7 फीसदी कर्मचारियों की भूमिकाओं में बदलाव करना पड़े गा। वहीं 88 फीसदी अे धिको रियों का कहना है कि वो अपने स्टाफ को दोबारा प्रशिक्षित करने की योजना बना रहे हैं ताकि वे इस बदलते दौर में तकनीक के साथ तालमेल बिठा सकें।

रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि 81 फीसदी भारतीय एचआर लीडर्स मानते हैं कि एजेंटिक एआई के साथ काम करने के लिए सॉफ्ट स्किल्स जैसे टीमवर्क और कम्युनिकेशन अब और ज्यादा जरूरी हो गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एचआर लीडर्स का बड़ा तबका इस बदलाव को अपनाने को तैयार है। करीब 85 फीसदी भारतीय एचआर अधिकारी मानते हैं कि आने वाले पांच सालों में मानव कर्मचारी और डिजिटल एजेंट एक साथ मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा, 60 फीसदी से ज्यादा एचआर अधिकारियों का मानना है कि उनके कर्मचारी अभी भी यह नहीं समझते कि एआई उनकी नौकरी को किस तरह प्रभावित करेगा।

सेबी पूर्व प्रमुख के खिलाफ लोकपाल ने खारिज किए सभी आरोप

मुंबई।

सेबी की पूर्व प्रमुख माधबी पुरी बुच के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को भारत के लोकपाल ने खारिज कर दिया है। लोकपाल ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर बताया कि उन आरोपों में कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य नहीं मिले, और ये आरोप सिर्फ अनुमानों और धारणाओं पर आधारित थे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उनके पति धवल बुच के साथ जुड़े वित्तीय लेन-देन के संदेह और कई कंपनियों से कथित संबंधों के आरोप सामने आए थे। लेकिन लोकपाल ने इन सभी आरोपों को मान्यता से रखा इनकार कर दिया। जस्टिस ए.एम. खानविलकर की अध्यक्षता में छह सदस्यीय पीठ ने घोषणा की कि शिकायतें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत जांच योग्य नहीं हैं और कानूनी रूप से जांच शुरू करने की कोई पर्याप्त वजह नहीं है। इसके चलते सभी आरोप खारिज कर दिए गए हैं। लोकपाल ने यह उल्लेख किया कि उन्हें पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला, और इससे जांच की आधारिक निगरानी नहीं की जा सकती।

भारत, चालू वित्त वर्ष में तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा: आरबीआई

बैंकों को जोखिमों से निपटने की जरूरत

मुंबई।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में देश के वित्त वर्ष 2025-26 में भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाए रहने की संभावना जताई है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे, वित्तीय क्षेत्र की मजबूती और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता के चलते देश इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। आरबीआई ने बताया कि ग्लोबल वित्तीय बाजार में उत्पन्न अनिश्चितताओं को विकास का नकारात्मक जोखिम और मुद्रास्फीति का सकारात्मक पहलू माना जा रहा है। इसके साथ ही, रिपोर्ट ने बताया कि नवीनतम शुल्क नीतियों में बदलाव के परिणामस्वरूप वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के प्रभाव आ सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने लगातार दो समीक्षाओं में प्रमुख नीतिगत दरों में कटौती की है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में और भी मजबूती आ सकती है। रिपोर्ट में ब्याज दर के मामले में भी ध्यान दिया गया है और बताया गया है कि बैंकों को जोखिमों से निपटने की जरूरत है, खासकर मुनाफा मार्जिन में कमी को ध्यान में रखते हुए। आरबीआई ने व्यापार समझौतों और बातचीत के माध्यम से प्रभावों को संभालने की सलाह दी है, जिससे नए वित्त वर्ष में चालू खाता घाटा प्रबंधनीय हो सके।

शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद

मुम्बई।

भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को बढ़त पर बंद हुए। इसी के साथ ही पिछले दो दिनो से जारी गिरावट रुक गयी। बाजार में ये तेजी दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीददारी ह्मवी रहने से आई है। आज सबह बाजार तेजी के साथ खुला वहीं दोपहर में बाजार में सपाट कारोबार हो रहा था पर अंत में निवेशकों की भारी खरीदारी से बाजार ऊपर आया।

दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 320.70 अंक (0.39 फीसदी की बढ़त के साथ ही 81,633.02 अंकों पर बंद हुआ। वहीं इसी प्रकार 50 शेयरों वाला एनएसई का निफ्टी 81.15 अंकों 0.33त्न बढ़कर 24,833.60 अंकों पर बंद हुआ।

आज सेंसेक्स की 30 में से 24 कंपनियों के शेयर लाभ के साथ ही ऊपर आकर बंद हुए। वहीं शेष 6 कंपनियों के शेयर नीचे आये। दूसरी ओर, आज निफ्टी 50 की 50 में से 37 कंपनियों के शेयरों में बढ़त रही। वहीं शेष 13 कंपनियों के शेयर नीचे आये। आज सेंसेक्स की कंपनियों में शामिल इंडसइंड बैंक के शेयर सबसे ज्यादा 2.49 फीसदी की बढ़त के साथ रहीजबकि बजाज फाइनेंस के शेयर सबसे ज्यादा 0.60 फीसदी नीचे आये।

सेंसेक्स में शामिल अन्य कंपनियों में आज सनफार्मा के शेयर 2.11 फीसदी, एटरनल (जोमेटो) 1.83 फीसदी, अडाणी पोर्ट्स 1.78, टाटा स्टील 1.27, टेक महिंद्रा 1.24, एक्सिस बैंक 1.15, टाटा मोटर्स 1.05, कोटक महिंद्रा बैंक 0.97, इंफोसिस 0.95, एचडीएफसी बैंक 0.75, महिंद्रा एंड महिंद्रा 0.73, मारुति सुजुकी 0.69, पावरग्रिड 0.62, टाइटन 0.57 फीसदी की फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं दूसरी ओर बजाज फिनसर्व के शेयर 0.30 फीसदी, एशियन पेंट्स 0.21, आईटीसी 0.17, टीसीएस 0.15 और एनटीपीसी के शेयर 0.06 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुए।

प्रीपेड यूजर्स के लिए रिलायंस जियो ने पेश किए 5 नए प्रीपेड प्लान्स

नई दिल्ली।

गेमिंग के शोकीन प्रीपेड यूजर्स के लिए रिलायंस जियो ने 5 नए प्रीपेड प्लान्स पेश किए हैं। जियो की वेबसाइट पर लिस्टेड इन प्लान्स की कीमत 48, 98, 298, 495 और 545 रुपए हैं। इन हाई स्पीड डेटा प्लान्स का फायदा उन यूजर्स को होगा, जो बिना गेम डाउनलोड किए सीधे क्लाउड के जरिए गेम खेलना चाहते हैं। क्योंकि, इन प्लान्स के साथ यूजर्स को जियो गेम्स क्लाउड का फ्री एक्सेस भी मिलेगा।

जियो गेम्स क्लाउड की प्रो पास की कीमत रुपए 398 है और इसकी वैलिडिटी 28 दिन की होती है। लेकिन, इन नए प्लान्स के साथ यूजर्स को यह सर्विस फ्री मिलेगी। बता दें कि, जियो गेम्स क्लाउड रिलायंस की क्लाउड गेमिंग सर्विस है, जो यूजर्स को पीसी, जियो सेट-टॉप बॉक्स और स्मार्टफोन पर प्रीमियम गेम्स खेलने की सुविधा देती है। भारत में इंटरनेट डेटा की खपत बढ़ी, गांवों में सबसे ज्यादा डिमांड ट्राई की मार्च-2025 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इंटरनेट और मोबाइल डेटा की खपत लगातार तेजी से

बढ़ रही है। खासतौर पर गांवों और छोटे कस्बों में मोबाइल और 5जी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सर्विस की डिमांड में बड़ी है।

ट्राई के मुताबिक, भारत में वायरलेस सब्सक्राइबर बेस यूजर्स की संख्या 116.03 करोड़ से बढ़कर 116,37 करोड़ हो गई है। इसमें मोबाइल और 5लर फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सर्विस दोनों कनेक्शन शामिल हैं।सिर्फ मोबाइल यूजर्स की संख्या फरवरी के 115.40 करोड़ से बढ़कर मार्च में 115.69 करोड़ हो गई है। वहीं, 5जी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सब्सक्राइबर संख्या बढ़कर 68 लाख हो गई, जिसमें सबसे बड़ा योगदान जियो का रहा है।

इंडसइंड बैंक के पांच अधिकारियों के खिलाफ इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप

अधिकारियों के बैंक खातों को भी किया फीज

मुंबई।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इंडसइंड बैंक के पूर्व सीईओ सुमंत कठपालिया सहित पांच वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ इनसाइडर ट्रेडिंग के गंभीर आरोपों के चलते कड़ी कार्रवाई की है। सेबी की जांच में परिणाम सामने आने के बाद बैंक के शेयरों में तेज़ गिरावट आई थी। सेबी ने पांच अधिकारियों के खिलाफ शेयर बाजार में ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाया है और उनके बैंक खातों को फीज कर दिया है। इसके साथ ही सेबी ने 19.7 करोड़ रुपए के अवैध लाभ को भी जब्त करने का आदेश दिया है। इंडसइंड बैंक द्वारा 1,529 करोड़ रुपए के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी के खुलासे के बाद सेबी ने यह जांच शुरू की थी। इस घटना के परिणामस्वरूप सभी पांच अधिकारियों पर आगे की कार्रवाई तक सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग से रोक लगाई गई है। इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों के चलते इंडसइंड बैंक एक बार फिर विवादों के घेरे में है, जिससे बैंक की सार्वजनिक छवि पर सवाल उठ रहे हैं।

टीसीएस के सीईओ को सैलरी पैकेज 26.52 करोड़ मिला

सैलरी में 1.39 करोड़ वेतन, 2.13 करोड़ लाभ, भत्ते एवं सुविधाएं शामिल

नई दिल्ली।

देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के सीईओ और एमडी के. कृतिवासन को वित्त वर्ष 2024-25 में 26.52 करोड़ रुपये का वेतन मिला है। यह वित्त वर्ष 2023-24 के मुकाबले 4.6 प्रतिशत अधिक है। कृतिवासन के सैलरी में 1.39 करोड़ रुपये का वेतन, 2.13 करोड़ रुपये के लाभ, भत्ते एवं सुविधाएं, 23 करोड़ रुपये का कमीशन शामिल है। वित्त वर्ष 2024 तक एचसीएलटेक के सीईओ सी. विजयकुमार सबसे अधिक वेतन पाने वाले भारतीय आईटी सीईओ थे। विजयकुमार को 84.16 करोड़ रुपये सैलरी पैकेज मिला। इसी तरह, इंफोसिस के सीईओ सलिल पारेख ने वित्त वर्ष 24 में 66.25 करोड़ रुपये कमाए, जबकि विप्रो के नवनियुक्त सीईओ श्रीनि पल्लिया को 50 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का पैकेज मिला। बता दें कि श्रीनि पल्लिया की इसी साल नियुक्ति हुई है। वहीं अन्य आईटी कंपनियों ने लेटेस्ट सैलरी ब्रेकअप को अपडेट नहीं किया है। टीसीएस की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि के. कृतिवासन को मिलने वाला वेतन कंपनी द्वारा अपने 6.07 लाख कर्मचारियों को दिए जाने वाले एवरेज सैलरी का लगभग 330 गुना है। वहीं टीसीएस के सीएफओ समीर सेकसरिया के कुल पारिश्रमिक में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कंपनी के मुताबिक, प्रमोशन के बाद कर्मचारियों के पारिश्रमिक में औसत वार्षिक वृद्धि 5.5 से 7.5 प्रतिशत के बीच रही। इस वर्ष 1.1 लाख कर्मचारियों को प्रमोट किया गया।

आरबीआई का बही-खाता वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 76.25 लाख करोड़ हुआ

31 मार्च 2024 तक 70,47,703.21 करोड़ रुपये था

मुंबई।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का 31 मार्च 2025 तक बही-खाते का आकार सालाना आधार पर 8.20 प्रतिशत बढ़कर 76.25 लाख करोड़ रुपये हो गया।` जिसकी वजह से केंद्र सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपये का भारी लाभ हो सिल हुआ है। आरबीआई की गुरुवार को जारी वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि संपत्ति के मामले में वृद्धि सोने, घरेलू निवेश एवं विदेशी निवेश में क्रमशः 52.09 प्रतिशत, 14.32 प्रतिशत और 1.70 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई। इस दौरान आय में 22.77 प्रतिशत और व्यय में 7.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष का अंत 2,68,590.07 करोड़ रुपये के समग्र अधिशेष के साथ हुआ जबकि पिछले वर्ष यह 2,10,873.99 करोड़ रुपये था, जिसके परिणामस्वरूप 27.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार बही-खाते का आकार 5,77,718.72 करोड़ रुपये या 8.20 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2025 तक 76,25,421.93 करोड़ रुपये हो गया। यह 31 मार्च 2024 तक 70,47,703.21 करोड़ रुपये था। देनदारियों के संबंध में आरबीआई ने कहा कि यह वृद्धि जारी नोट, पुनर्मूल्यांकन खातों एवं अन्य देनदारियों में क्रमशः 6.03 प्रतिशत, 17.32 प्रतिशत और 23.31 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई। रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक घरेलू परिसंपत्तियों का हिस्सा 25.73 प्रतिशत था। वहीं विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना तथा भारत के बाहर वित्तीय संस्थानों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम राशि कुल परिसंपत्तियों का 74.27 प्रतिशत थीं। वहीं 31 मार्च 2024 तक यह क्रमशः 23.31 प्रतिशत और 76.69 प्रतिशत थी। इसमें कहा गया है कि 44,861.70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और उसे आकस्मिकता निधि (सीएफ) में स्थानांतरित कर दिया गया।

मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट्स से वसूले जाने वाले शुल्क एक समान हो: एएएचएल

मुंबई।

अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) ने सरकार से मांग की है` कि मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट्स को एक ही जोन या यूनिट की तरह ट्रीट किया जाए, ताकि दोनों जगह यात्रियों और एयरलाइनों से वसूले जाने वाले शुल्क एक जैसे हों। कंपनी ने इस बारे में सरकार को प्रस्ताव भेजा है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो दोनों एयरपोर्ट्स पर लगने वाले शुल्क में समानता आ जाएगी। इससे नवी मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है, जो कि एएएचएल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कंपनी ने करीब 16,700 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। हालांकि दोनों एयरपोर्ट्स अडानी ग्रुप के ही हैं, लेकिन नवी मुंबई एयरपोर्ट पर फिलहाल पैसेंजर फीस और एयरलाइन चार्जेस कहीं ज्यादा तय किए गए हैं। यही वजह है कि एयरलाइंस वहां शिफ्ट होने से हिचकिचा सकती हैं। दरअसल, नवी मुंबई एयरपोर्ट जुलाई से कमर्शियल उड़ानों के लिए खुलने वाला है। अडानी ग्रुप ने सरकार से कहा है कि मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट को एक ही एयरपोर्ट मानकर वहां लगने वाले चार्ज तय किए जाएं। इसके लिए उन्होंने 2021 में एयरपोर्ट रेगुलेटरी में किए गए बदलाव का हवाला दिया है। इस बदलाव के तहत एक बड़े एयरपोर्ट के साथ छोटे और घाटे में चल रहे एयरपोर्ट्स को जोड़कर एक साथ प्राइवेट कंपनियों को दिया जा सकता है, ताकि निवेशक उसमें दिलचस्पी लें।

खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी बढ़ी

किसान क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज में मिलेगा लोन

नई दिल्ली।

केंद्र सरकार ने धान, कपास, सोयाबीन, अरहर समेत खरीफ की 14 फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) बढ़ा दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दी है। धान की नई एमएसपी 2,369 रुपए तय की गई है, जो पिछली एमएसपी से 69 रुपए ज्यादा है। कपास की नई एमएसपी 7,710 रुपए तय की गई है और इसकी एक दूसरी किस्म की नई एमएसपी 8,110 रुपए हो गई है।

नई एमएसपी से सरकार पर 2 लाख 7 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इससे पहले की तुलना में यह 7 हजार करोड़ रुपए ज्यादा है।

मंत्री ने बताया कि एमएसपी फसल की लागत से कम से कम 50 फीसदी ज्यादा होना चाहिए। इस फैसले के साथ ही किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज सब्सिडी योजना को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस योजना की जानकारी के मुताबिक किसान केसीसी से 3 लाख रुपए तक का लोन 7 फीसदी ब्याज पर ले सकेंगे, जिसमें बैंकों को 1.5 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलेगी। अगर किसान समय पर चुका देते हैं लोन तो 3 फीसदी तक का प्रोत्साहन भी मिलेगा, जिससे उनका ब्याज मात्र 4 फीसदी रह जाएगा। सरकार ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो कुल अनुमानित लागत 3,399 करोड़ रुपए है। ये परियोजना 2029-30 तक पूरी की जाएंगी। किसी भी देश के विकास के लिए कृषि और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इससे सरकार के विकास और किसानों के लिए सुधार की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है।

तेजी से फैल रहा कोरोनाः 12 सौ से ज्यादा हुए मरीज, 12 की गई जान

नई दिल्ली।

देशभर में कोरोना वायरस फिर से पैर पसारने लगा है। नए वैरिएंट की चपेट में हर दिन नए लोग आ रहे हैं। अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में नए कोरोना से संक्रमित नए मरीजों की संख्या 1200 का क्रॉस कर चुकी है। कोविड-19 के पॉजिटिव मरीजों में से 12 की मौत हो चुकी है। केरल में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। स्थिति को देखते हुए सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी जरूरी चीजों का पर्याप्त स्टॉक रखने की भी सलाह दी गई है, ताकि प्रतिकूल हालात में भी स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके।कोरोना के नए वैरिएंट ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। रोजाना दर्जनों नए मामले सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की ओर से हेल्थ डिपार्टमेंट को निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट रहने और कोरोना से जुड़ी चीजों (जैसे दवाई, ऑक्सीजन सिलेंडर) का स्टॉक रखने और उसकी मॉनिटरिंग करने को भी कहा है। दिल्ली से लेकर हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में कोरोना संक्रमण के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने जनता और स्वास्थ्य अधिकारियों से कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के बारे में सतर्क और सक्रिय रहने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री राव ने यह भी कहा कि समय पर कार्रवाई और निवारक उपायों का सख्ती से पालन करने से वायरस के प्रसार को काफी हद तक रोका जा सकता है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाल ही में हरियाणा में कुल 16 कोविड मामले सामने आए हैं।

केरल में 400 से अधिक हुए संक्रमित

केरल एक बार फिर से नए वैरिएंट से संक्रमितों की संख्या में मामले में हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। केरल में अभी तक 400 से भी ज्यादा नए कोरोना मरीजों की पहचान की जा चुकी है। ऐसे में राज्य में और भी सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही टेस्टिंग प्रोसेस भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। आम से लेकर खास तक कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं।

पटना में भी कोरोना के 10 नए मामले

पटना में 4 और लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 10 हो गई है। पटना के जिला मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि सभी मरीजों में संक्रमण का स्तर बहुत हल्का है और सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनकी बारीकी से निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा, अब पटना में कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित लोगों की कुल संख्या 10 हो गई है।

उन्होंने आगे कहा, 'हम नागरिकों से सतर्क रहने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य प्रणाली स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।' पटना के डीएम ने कहा कि शहर के सरकारी अस्पतालों को तैयार रहने और बिस्तर, ऑक्सीजन, दवाओं और टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

पिछले कुछ हफ्तों में देश भर में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिनमें से अधिकांश रोगियों में हल्के लक्षण हैं और वे घर पर ही ठीक हो रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

चारधाम यात्रा में क्यों आ रहा हार्ट अटैक, डॉक्टरों से जाने वजह

नई दिल्ली।

चारधाम यात्रा, श्रद्धा और आस्था का वहां सफर है इसे हर हिंदू जीवन में एक बार करना चाहता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक सवाल बार-बार उठ रहा है कि आखिर इस यात्रा में हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? इस पर डॉक्टरों की राय जानना बेहद जरूरी है। दरअसल चारधाम की यात्रा समुद्र तट से 8,000 से 12,000 फीट तक की ऊंचाई पर होती है, जहां हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वहीं कई लोग बिना मेडिकल चेकअप के यात्रा शुरू कर देते हैं, जिन्हें पहले से दिल की समस्या होती है। चारधाम यात्रा में लंबे समय तक चलना, सीढ़ियां चढ़ना और ठंड का सामना करना होता है। ठंड और ऑक्सीजन कम होने की वजह से ऊंचाई पर ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ सकता है, जिससे दिल पर तनाव होता है। पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित होती हैं और हार्ट अटैक के समय इलाज मिल पाना मुश्किल होता है। डॉक्टरों की सलाह है कि 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को यात्रा से पहले बीपी और ब्लड टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए।

1700 साल पुरानी शिव पार्वती की दुर्लभ मूर्ति

जमुई। बिहार के जमुई जिले के मंजोस गांव मे शिव पार्वती की एक दुर्लभ मूर्ति प्राप्त हुई है। इसे 1700 से 1800 वर्ष पुरानी प्रतिमा बताई जा रही है। यह मूर्ति उमा- महेश्वर रूप में है। शिव-पार्वती एक साथ विराजमान हैं। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार यह मूर्ति पाल वंश के समय की बताई जा रही है। इस ऐतिहासिक मूर्ति को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में टकराव उत्पन्न हो गया है। मूर्ति मिलने की जानकारी पर एसडीओ, एसडीओपी एवं अन्य अधिकारी पहुंचे। उन्होंने मूर्ति को म्यूजियम में रखने के लिए मूर्ति की मांग की। ग्रामीणों ने मूर्ति देने से इनकार कर दिया। प्रशासन का कहना है, यह राष्ट्रीय धरोहर है। वहीं ग्रामीण मूर्ति के प्रति अपनी धार्मिक आस्था के कारण गांव के मंदिर में ही इसकी पूजा पाठ करना चाहते हैं। जिसके कारण विवाद का विषय बना हुआ है।

16 साल का किसान पुत्र पढ़ेगा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में

मुंबई।

महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के एक छोटे से गांव का विवेक हनुमंत सुतार ने दसवीं की पढ़ाई के दौरान दो किताबें लिखी। पढ़ाई के साथ-साथ वह खेतों मे भी काम कर रहा था। किताब भी लिख रहा था। उसकी मेहनत के चर्चे और लगन की जानकारी जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिली। किसान पुत्र को यह मौका इंटरनेशनल बेकलारिएट कोर्स के माध्यम से मिला। जिसमें उसने शानदार प्रदर्शन किया। सामाजिक कार्यों और अलग-अलग गतिविधियों में जो जानकारी उसने प्रस्तुत की।उसके बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने पढ़ने के लिए बुला लिया। 16 साल की उम्र में गांव के एक साधारण किसान का लड़का अब अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेगा। इसकी पढ़ाई का पूरा खर्च यूनिवर्सिटी उठाएगी।

ऑपरेशन सिंदूर का 10 साल का योद्धा

चंडीगढ़।

पंजाब के फिरोजपुर जिले के तारावाली गांव के 10 साल के बच्चे स्वर्ण सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में एक योद्धा के रूप में काम किया है। 10 साल की उम्र का यह बच्चा गोलीबारी के बीच भारतीय जवानों को दूध, लस्सी और ठंडा पानी पहुंचा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त होने के बाद इसे सार्वजनिक रूप से सबसे कम उम्र का नागरिक योद्धा घोषित कर सम्मानित किया गया है। 10 साल के इस बच्चे में राष्ट्रहित को लेकर जुनून है। यह बड़ा होकर फौज में भर्ती होना चाहता है।

ऑपरेशन सिंदूर का 10 साल का योद्धा

चंडीगढ़।

पंजाब के फिरोजपुर जिले के तारावाली गांव के 10 साल के बच्चे स्वर्ण सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में एक योद्धा के रूप में काम किया है। 10 साल की उम्र का यह बच्चा गोलीबारी के बीच भारतीय जवानों को दूध, लस्सी और ठंडा पानी पहुंचा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त होने के बाद इसे सार्वजनिक रूप से सबसे कम उम्र का नागरिक योद्धा घोषित कर सम्मानित किया गया है। 10 साल के इस बच्चे में राष्ट्रहित को लेकर जुनून है। यह बड़ा होकर फौज में भर्ती होना चाहता है।

देश की सुरक्षा ही नहीं, सीमावर्ती इलाकों के बच्चों का भविष्य भी संवार रही सेना

रिमोट एरिया के बच्चों को फ्री कोचिंग मिल रही

नई दिल्ली।

लेह से करीब 45 किलोमीटर दूर बसा एक गांव सक्थी है। 11 साल की जिगमेत डेकी जब 2021 में अपने पिता ताशी पालजोर के साथ पहली बार दिल्ली घूमने आई, तब पिता को एहसास हुआ कि जिगमेत को वहां नहीं मिल पा रहा, जो मिलना चाहिए। ताशी कहते हैं कि जिगमेत बचपन से ही पढ़ाई ध्यान से करती थी। लेकिन हमारे गांव से निकलकर वह देश भर में चमके, ऐसा सपना देखने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन ताशी की उम्मीदों को अब पंख लगे हैं। जिगमेत सहित लेह से लेकर अरुणाचल के रिमोट एरिया के बच्चों को फ्री कोचिंग मिल रही है। भारतीय सेना बॉर्डर के इलाकों में सिर्फ सुरक्षा ही नहीं कर रही बल्कि बच्चों का भविष्य भी संवार रही है।जिगमेत के स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि सेना बच्चों को फ्री कोचिंग करा रही है। मुझे लगा कि ये जिगमेत के भविष्य के लिए अच्छा है। स्कूल के बाद हर रोज सेना के इंस्ट्रक्टर बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। इसका नतीजा भी दिखा, जब ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के इंटरेंस एग्जाम का रिजल्ट आया। लद्दाख में भारतीय सेना की त्रिशूल डिविजन और सियाचीन ब्रिगेड की कोचिंग क्लास में अध्ययनरत 66 बच्चों में से 46 बच्चे इस ऑल इंडिया एग्जाम में पास हुए है। इसी तरह सेना की गजराज कोर भी अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले के दूरस्थ गांव जांग और दिरांग के 44 बच्चों को फ्री कोचिंग दे रही है। इसमें से 38 छात्रों ने इस साल का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का इंटरेंस एग्जाम पास किया है। जिगमेत की तरह ये सभी बच्चे अब अपने इलाके के उन सभी बच्चों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं जिन्हें लगता था कि वह राष्ट्रीय स्तर पर कैसे मुकाबला कर सकते है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सेना न सिर्फ इन्हें पढ़ाई में मार्गदर्शन दे रही है बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा रही है और अनुशासन सिखा रही है। बच्चों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का जज्बा भी दे रही है।

पटना में पीएम मोदी का रोड शो, लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह

एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन

पटना।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को पटना में भव्य रोड शो किया, जिसमें हजारों लोग तिरंगा लेकर सड़क किनारे उनका स्वागत करते नजर आए। पीएम मोदी ने गाड़ी से ही लोगों का अभिवादन किया और जनता का उत्साह बढ़ाया।

इस रोड शो से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। उन्होंने बिहटा एयरपोर्ट का वर्चुअल शिलान्यास भी किया। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के साथ ही राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो की लंबाई करीब 6 किलोमीटर रही। रोड शो की सुरक्षाव्यवस्था में 3000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। इसी के साथ रोड शो के रास्ते 32 जगहों पर स्वागत मंच भी बनाए गए थे। पीएम मोदी की यह यात्रा आरण्य भवन से शुरू होकर बीजेपी कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ पर खत्म हुई।

पीएम मोदी रोड शो के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अगले दिन यानी 30 मई को वे रोहतास में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा को लेकर वहां खास तैयारियां की जा रही हैं।

महिलाओं ने किया पारंपरिक स्वागत

रोहतास में महिलाओं ने एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर पारंपरिक गीत गाए। यह प्रधानमंत्री मोदी के ऑपरेशन सिंदूर के बाद का पहला

बिहार दौरा है। इससे पहले 24 अप्रैल को मधुबनी में उन्होंने आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया था। पटना में आज का दिन उत्साह और देशभक्ति से भरा नजर आ रहा, जहां लोगों ने पूरे जोश से प्रधानमंत्री का स्वागत किया है।

केंद्र के आदेश के बाद नागरिक मॉक ड्रिल स्थगित

नई दिल्ली।

देश के सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गुरुवार को नागरिक मॉक ड्रिल होनी थी। लेकिन स्थगति किया गया है। इस मॉक ड्रिल को प्रशासनिक कारणों से स्थगित किया गया है। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य है कि पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव की स्थिति को देखकर आपातकालीन तैयारियों को मजबूत किया जाए। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब सहित कई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश जैसे चंडीगढ़ में बुधवार देर शाम आधिकारिक तौर पर मॉक ड्रिल स्थगित कर दी है।

ये फैसला प्रशासनिक कारणों से लिया गया है। इस मॉक ड्रिल के स्थगित होने पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। हरियाणा गृह विभाग की ओर से स्थगन की पुष्टि की गई है। बयान में कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार हरियाणा गृह विभाग ने व्यापक नागरिक सुरक्षा अभ्यास, ऑपरेशन शील्ड को स्थगित करने की घोषणा की है।

चंडीगढ़ प्रशासन ने स्पष्ट किया कि गुरुवार को कोई ब्लैकआउट या मॉक ड्रिल नहीं होगी। इस फैसले का श्रेय भारत सरकार के निर्देशों को दिया। ऑपरेशन शील्ड को शुरू में हरियाणा के सभी 22 जिलों में शाम 5 बजे से 9 बजे के बीच आयोजित किया जाना था। राजस्थान में सभी 41 जिलों में एक व्यापक मॉक ड्रिल की योजना बनाई थी, ने भी स्थगन का इसी प्रकार का आदेश जारी किया। राज्य के गृह विभाग के एक बयान के अनुसार, अभ्यास की नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। केंद्र से निर्देश मिलने के समय ही जैसलमेर और बाड़मेर जैसे सीमावर्ती जिलों में सायरन बजाने

और विशेष व्यवस्था सहित अभ्यास की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं।

पंजाब ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया तथा अपने नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण अभ्यास को पुनर्निर्धारित करने का सक्रिय अनुरोध किया। केंद्र ने 3 जून को अभ्यास आयोजित करने के पंजाब के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है तथा उपायुक्तों को संशोधित तिथि के बारे में सूचित कर दिया गया है।

अब भारत बनाएगा 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट, एएमसीए ने दी मंजूरी

यह दो वेरिएंट्स–मार्क 1 और मार्क 2 के रूप में किया जाएगा तैयार

नई दिल्ली।

भारत अब 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट वाले देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बन जाएगा, जो खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान विकसित करेगा। भारत का यह फाइटर जेट प्रोजेक्ट एडवांड मिडियम कोमबेट एयरक्राफ्ट (एएमसीए) नाम से जाना जाता है। इसे दो वेरिएंट्स–मार्क 1 और मार्क 2–के रूप में तैयार किया जाएगा। इस विमान को एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) मिलकर विकसित कर रहे हैं। एएमसीए मार्क 1 अमेरिकी इंजन जीई-एफ414 से चलेगा और पूरी तरह स्टील्थ तकनीक से लैस होगा। इसका प्रोटोटाइप 2028 तक तैयार होने की उम्मीद है। वहीं एएमसीए मार्क 2 में भारत का खुद का इंजन लगाया जाएगा, जिसे विदेशी कंपनियों के सहयोग से बनाया जाएगा। इसमें कुछ 6वीं पीढ़ी की तकनीकें भी शामिल होंगी। इस प्रोजेक्ट

की कुल लागत करीब 15,000 करोड़ रुपए है और इसका लक्ष्य 2035 तक बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करना है। एएमसीए से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य ताकत के मुकाबले भारत के पास स्टेल्थ जेट होना जरूरी है। भारत की वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, जबकि वर्तमान में सिर्फ 30 स्क्वाड्रन हैं। एएमसीए प्रोजेक्ट से इस कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को हाल ही में रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है और काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।

रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख को दीक्षा देकर दक्षिणा में मांग लिया पीओके

चित्रकूट।

सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी बुधवार को चित्रकूट गए थे। सुबह भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट में दर्शन करने के बाद वह जगदुरु रामभद्राचार्य के आश्रम भी गए। यहां उन्होंने रामभद्राचार्य से दीक्षा भी ली थी। रामभद्राचार्य महाराज ने उन्हें दीक्षा देने के बाद बताया कि मैंने उनसे दक्षिणा भी मांगी है,जिसमें मैंने उनसे पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर मांगा है। सेना प्रमुख के चित्रकूट में उनके आश्रम जाने पर आध्यात्मिक गुरु जगदुरु रामभद्राचार्य ने बताया कि मैंने उन्हें वही दीक्षा राम मंत्र के साथ दी,जो भगवान हनुमान को मां सीता से मिली थी और फिर उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी। मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके वापस चाहिए। भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार की सुबह भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे। उन्होंने पत्नी के साथ तुलसीपीठ पहुंचकर कांच मंदिर में पूजा-अर्चन किया। इसके बाद तुलसी पीठाधीश्वर जगदुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। सेना प्रमुख

जगदुरु से गुरु दीक्षा भी ली। सेनाध्यक्ष के आगमन पर धर्मनगरी सेना की छावनी में तब्दील नजर आया। कई जगह बैरियर लगाकर लोगों को आवागमन रोका गया। सदुरु नेत्र चिकित्सालय जानकीकुंड में इलाज कराने के लिए आने-जाने वाले लोगों को भी रोकने से दिक्कतें हुई। सेना के जवान हर जगह सुरक्षा में मुस्तैद रहे। एमपी पुलिस के अधिकारी भी सुरक्षा को देखते डटे रहे। हेलीपैड से कड़ी सुरक्षा बीच सेना प्रमुख का काफिला जगदुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज की तुलसीपीठ पहुंचा। यहां सेना प्रमुख ने कांच मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की।

थियेटर कमांड से तीनों सेनाओं में और अधिक बढ़ेगी एकजुटता, सुनिश्चित होगी कमांड दक्षता

नई दिल्ली।

पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने थियेटर कमांड (सेना, वायुसेना, नौसेना की संयुक्त कमांड) के गठन की प्रारंभिक कवायद से जुड़े अंतर सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम-2023 के तहत तैयार किए गए नियमों को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है।

जो कि बीते मंगलवार (27 मई) से प्रभावी होंगे। इसके पीछे उद्देश्य अंतर-सेवा-संगठनों (आईएसओ) की प्रभावी कमान, नियंत्रण और कुशल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के अलावा सशस्त्र सेनाओं के बीच एकजुटता व कमांड दक्षता सुनिश्चित किया जाना है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। गौरतलब है कि यह नियम सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त थियेटर कमांड का गठन हो जाने पर काफी मददगार साबित होंगे। वर्तमान में यह कानून और नियम सशस्त्र सेनाओं की अंडमान-निकोबार स्थित त्रि-स्तरीय कमांड से लेकर अंतर सेवा संगठन के रूप में कार्य कर रहे तमाम सैन्य संगठनों, प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे। मंत्रालय ने कहा, नियमों की अधिसूचना के साथ ही यह अधिनियम अब पूरी तरह से लागू हो गया है।

जिससे आईएसओ के प्रमुखों को अधिकार प्राप्त होंगे, अनुशासनात्मक मामलों का शीघ्र निपटारा संभव हो सकेगा और कार्यवाही के दोहराव से बचने में मदद मिलेगी।

अधिनियम 10 मई 2024 से लागू हुआ

मंत्रालय ने बताया कि अंतर सेवा संगठन अधिनियम-2023 को संसद के मॉनसून सत्र के दौरान दोनों सदनों (लोकसभा, राज्यसभा) द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद उसी वर्ष 15 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी मंजूरी प्रदान की। फिर इसके अगले साल 8 मई 2024 को राजपत्र अधिसूचना से यह अधिनियम 10 मई 2024 से लागू हो गया। इसके बाद आईएसओ को 27 दिसंबर 2024 के राजपत्र अधिसूचना संख्या एसआरओ 72 के जरिए अधिसूचित किया गया।

वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बढ़ेगी शक्ति

अधिनियम के जरिए अंतर सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ और ऑफिसर-इन-कमांड को अपने अधीन सेवारत कर्मियों पर नियंत्रण करने का पूर्ण अधिकार मिलेगा। जिससे संगठनों के अंदर अनुशासन और प्रशासन सुनिश्चित होता है।

अधिनियम की एक खास बात यह है कि इसके जरिए सशस्त्र बलों की प्रत्येक शाखा पर लागू विशिष्ट सेवा शर्तों में बिना किसी बदलाव के यह लागू होगा।

भारत-नेपाल सीमा पर भारतीय वाहनों की नो इंट्री, लगा लंबा जाम, मची अफरा-तफरी

पटना।

नेपाल के भंसार कार्यालयों के बंद होने से भारतीय वाहनों को सीमा पार करने के लिए जरूरी रोड परमिट और कस्टम औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। भारतीय नंबर प्लेट वाले गाड़ियों को नेपाल में एंट्री से रोक लिया गया है। सीमा पर तैनात अधिकारियों ने बताया कि यह बंदी केवल एक दिन के लिए है, और अगले दिन सामान्य गतिविधियां बहाल हो सकती हैं। हालांकि, इस अचानक फैसले ने सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापारियों और स्थानीय लोगों में निराशा पैदा की है। खासकर, उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में व्यापार पर इसका तत्काल प्रभाव देखा जा रहा है।

सीमा पर फंसे एक भारतीय व्यापारी ने बताया कि भंसार कार्यालय बंद होने से उनका माल नेपाल नहीं पहुंच पा रहा, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। वहीं, पर्यटकों का कहना है कि इस तरह की अचानक बंदी से उनकी यात्रा योजनाएं प्रभावित हुई हैं। नेपाल के पर्यटन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे ने हाल ही में भारतीय पर्यटकों की सुविधा के लिए एकीकृत प्रणाली लागू करने की बात कही थी, लेकिन इस बंदी ने उनकी योजनाओं पर सवाल उठाए हैं।भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा और रोटी-बेटी का रिश्ता ऐतिहासिक रहा है। दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा के एक-दूसरे के देश में जा सकते हैं। हालांकि, वाहनों के लिए भंसार शुल्क और रोड परमिट जैसे नियम लागू हैं। नेपाल सरकार ने हाल के वर्षों में भारतीय वाहनों पर भंसार शुल्क बढ़ाया है, जैसे कि 2019 में दोपहिया वाहनों का शुल्क 113 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये किया गया। 2024 में भी रोड परमिट के लिए भारतीय वाहनों को 1600 रुपये अतिरिक्त देने का नियम लागू हुआ, जिसका व्यापारियों ने विरोध किया था। पिछले कुछ वर्षों में भारत-नेपाल सीमा पर कई बार तनाव देखा गया है।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। मो. नं. 9928078717